दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका
नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 34 | मूल्य 05 रुपये | 11-17 जनवरी, 2026

मरीजो का खून चूस रहे है स्वास्थ्य के भगवान!

साइबर फ्रॉड एक चुनौती, सजगता है जरूरी

अंकिता भंडारी हत्याकांड सीबीआई जांच

पूर्ण न्याय की ओर सीएम धामी का फैसला

विज्ञान संप्रेषण

राष्ट्रीय मासिक वैज्ञानिक पत्रिका

ISSN: 2583-6064

निर्बन्धित अवकाश

__जनवरी__
गणतंत्र दिवस- 26 जनवरी
__फरवरी__
महा शिवरात्रि - 15 फरवरी
__मार्च__
होलिका दहन- 03 मार्च
होली - 04 मार्च
ईद-उल-फितर - 21 मार्च
रामनवमी- 26 मार्च
महावीर जयंती - 31 मार्च
__अप्रैल__
गुड फ्राइडे - 03 अप्रैल
डॉ बी आर आंबेडकर जयंती- 14 अप्रैल
__मई__
बुद्ध पूर्णिमा - 01 मई
ईद उल अजहा- 27 मई
__जून__
मोहर्रम - 26 जून
__जुलाई__
हरेला - 16 जुलाई
__अगस्त__
स्वतंत्रता दिवस - 15 अगस्त
ईद उल मिलाद- 26 अगस्त
रक्षा बंधन- 28 अगस्त
__सितम्बर__
जन्माष्टमी- 04 सितंबर
__अक्तूबर__
गांधी जयंती - 02 अक्तूबर
दशहरा - 20 अक्तूबर
महर्षि वाल्मीकि जयंती- 26 अक्तूबर
__नवम्बर__
दीपावली- 08 नवंबर
गोवर्द्धन पूजा - 10 नवंबर
ईगास-बग्वाल - 20 नवंबर
गुरु नानक जयंती - 24 नवंबर
__दिसम्बर__
क्रिसमस - 25 दिसंबर

2026

JANUARY

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

FEBRUARY

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

MARCH

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

APRIL

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MAY

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

JUNE

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

JULY

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

AUGUST

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

SEPTEMBER

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

OCTOBER

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

NOVEMBER

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

DECEMBER

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

विज्ञान संप्रेषण परिवार की ओर से सभी पाठकों ओर लेखकों को

2026 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

अपने नजदीकी बुक स्टॉल से मांगे

अथवा पत्रिका की वार्षिक सदस्यता के लिए हमे लिखें subscription.vigyan@gmail.com

संपादकीय कार्यालय: 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल: +91 8433456398, 9027361913 | Email: subscription.vigyan@gmail.com

वर्ष 15 | अंक 34

दिव्य हिमगिरि

11-17 जनवरी, 2026

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*
*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

किराया बढ़ा लेकिन सुविधाओं की जगह शिकायतें बढ़ी

भारत में रेल सेवा आर्थिक विकास के साथ-साथ आम लोगों के सफर को आसान और सुगम बनाने की जीवन रेखा मानी जाती है। लंबी यात्रा के लिए रेलगाड़ियां ही एकमात्र किफायती साधन हैं। देश में रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण को लेकर एक तरफ सरकार की ओर से नई-नई घोषणाएं और दावे किए जाते हैं, तो दूसरी ओर रेलगाड़ियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव जस का तस बना हुआ है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेलगाड़ियों में साफ-सफाई की माकूल व्यवस्था न होने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। रेल मद्द पोर्टल पर दर्ज इस तरह की शिकायतों में सितंबर 2025 की तुलना में अक्तूबर और नवंबर में लगभग पचास फीसद की वृद्धि देखी गई है। इससे स्पष्ट है कि व्यवस्थागत खामियों और सरकारी अमले में विभिन्न स्तर पर लापरवाही की वजह से यात्रियों को सफर के दौरान कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि रेल किराए में सरकार जब चाहे बढ़ोतरी कर देती है। सवाल है कि किराए में वृद्धि के साथ क्या सुविधाओं में भी सुधार नहीं होना चाहिए? जब मौजूदा सुविधाएं ही बेहाल हों, तो ऐसे में आधुनिकीकरण के दावों का क्या औचित्य रह जाता है। गौरतलब है कि कैग की वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की एक रपट में भी लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ-सफाई की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे। इसमें कहा गया था कि इस व्यवस्थागत खामी के लिए संबंधित अधिकारियों की लापरवाही भी जिम्मेदार है। इसके अलावा साफ-सफाई से जुड़े रेल कर्मियों का अभाव और इस कार्य के लिए साजो-सामन की कमी की ओर भी इशारा किया गया था। हालांकि रेलवे ने कुछ खास स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के शौचालय, दरवाजे और कुछ अन्य हिस्सों की सफाई मशीनों से करने की योजना लागू की है, इसके बावजूद व्यवस्था में अपेक्षाजनक सुधार नजर नहीं आता है। रेलवे मंत्रालय की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, रेल मदद पोर्टल पर सितंबर 2025 में चादर और कंबल से संबंधित 8,758 शिकायतें मिली थीं, जो अक्तूबर में बढ़ कर 13,406 और नवंबर में 13,196 हो गईं। इसी तरह डिब्बों की स्वच्छता से जुड़ी शिकायतें सितंबर 2025 में 24,758 थीं, जो अक्तूबर में बढ़ कर 33,804 और नवंबर में 36,673 हो गईं। हाल में सरकार ने लंबी दूरी की रेल सेवाओं का किराया बढ़ाने की घोषणा की थी। हालांकि यह वृद्धि देखने में मामूली लगती है, लेकिन देश भर में प्रतिदिन रेल में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या की लिहाज से देखें, तो सरकार को हर साल इससे करोड़ों रुपए की कमाई होगी। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व अर्जित करना ही है? अगर ऐसा नहीं है, तो यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। रेल मद्द पोर्टल पर बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर मंत्रालय ने हाल में सभी मंडलों के अधिकारियों को पत्र भेज कर व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इन निर्देशों पर कड़ाई से अमल होगा या फिर महज खानापूर्ति का ही प्रयास किया जाएगा, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सवाल इसलिए अहम है, क्योंकि जब तक रेलगाड़ियों में साफ-सफाई और अन्य सुविधाओं को लेकर व्यापक निगरानी तंत्र विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक समस्या के स्थायी समाधान की उम्मीद करना व्यर्थ है।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

मरीजो का खून चूस रहे है स्वास्थ्य के भगवान!

डॉ श्रीगोपाल नारसन
एडवोकेट

देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक प्राइवेट अस्पताल ने सिर्फ इसलिए मरीज के शव को बंधक बना लिया क्योंकि उस अस्पताल की कुछ फीस मर गए मरीज पर बकाया थी। शव दिलाने के लिए पुलिस को अस्पताल पर मुकदमा दर्ज करना पड़ा, तब जाकर शव मुक्त हुआ और उसका अंतिम संस्कार हो सका। चिकित्सीय सेवाओं में चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे उत्तराखंड को राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा बहाल करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सको को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से भी ज्यादा वेतन 7 लाख रुपये प्रतिमाह का भुगतान करना पड़ रहा है। फिर भी चिकित्सको द्वारा सरकारी सेवा में रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस करने और दवा कम्पनियों से कमीशनखोरी के आरोप लगते रहे है। आपको बता दे कि देश मे 1.40 बिलियन लोगों के लिये सिर्फ 10 लाख पंजीकृत डॉक्टर हैं। यानि प्रत्येक 13 हजार नागरिकों पर मात्र एक डॉक्टर मौजूद है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संदर्भ में एक हजार व्यक्तियों पर एक चिकित्सक के अनुपात को जायज और जरूरी माना है। भारत के शहरी क्षेत्रों में 58 प्रतिशत योग्य चिकित्सक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आँकड़ा 19 प्रतिशत से भी कम है। योग्य चिकित्सकों के अभाव में देश में में झोलाछाप डाक्टरों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन झोलाछाप डॉक्टरों के कारण मरीजों की जान सासत में है। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के कारण झोलाछाप डाक्टर ही नही पंजीकृत डॉक्टर भी कमीशनखोरी की बदौलत चाँदी कूट रहे है। गावों में झोलाछाप डाक्टर सरेआम क्लीनिक चलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में 57.3 प्रतिशत डॉक्टर बिना मेडिकल डिग्री के हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, दिल्ली मेडिकल काउंसिल एक्ट 1997, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 में कहा गया है कि केवल एक रजिस्टर्ड डॉक्टर ही एलोपैथिक दवा लिख सकता है। "भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति के अभ्यासी के अलावा कोई भी व्यक्ति जो किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता रखता है और किसी राज्य रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा के केंद्रीय रजिस्टर में नामांकित है, भारतीय में मेडिकल और किसी भी राज्य में मरीजों के लिए दवा लिख सकेगा।

इनके अलावा यदि कोई ऐसा करता पाया तो उसके लिए इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 में कारावास की सजा का उल्लेख है जो एक वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना जो 1,000 रुपये तक हो सकता है या दोनों हो सकता है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1997 के तहत क्लॉज (27) में 'कठोर दंड' का उल्लेख किया गया है । इसमें तीन साल तक की कैद या 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते है। वही एक व्यक्ति ने बीती 7 अगस्त को दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियों से सवाल संख्या 67643 में पूछा कि एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर मरीज को देखने के बाद कुछ जांच लिखता है फिर वह रोगी जिस प्रयोगशाला में जाता है उसके संचालक इस जांच की वास्तविक राशि से दोगुना राशि लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस जांच का आधा मूल्य यानि कमीशन डॉक्टर को देना पड़ता है, और अगर कोई लैब डॉक्टर को हिस्सा न दे तो डॉक्टर उस लैब की जांच को गलत बताते हैं और उस प्रयोगशाला में फिर मरीज को नहीं जाने देते। इसी तरह मेडिकल स्टोरों से दवा लेने पर डॉक्टरो पर कमीशन लेने का आरोप हैं। अगर कोई मुस्लिम डॉक्टर लैब या मेडिकल स्टोर से दवा या परीक्षण के नाम पर कमीशन लेता है तो यह जायज है या नाजायज?। इस सवाल पर मुफ्तियों की खंडपीठ ने जवाब संख्या 67643 में कहा कि डॉक्टर लैब या मेडिकल स्टोर वालों से मरीज भेजने पर या मेडिकल स्टोर वालों की दवाईयां लिखने पर जो कमीशन लेते हैं, ये शरई में जायज नहीं है।

उन्होंने कहा कि किसी जमाने में हकीम लोग दवाई लिखने पर अत्तार यानि दवा विक्रेता से 25 प्रतिशत या उससे कम कमीशन लेते थे। हमारे हजरात अकाबिरे उलेमा देवबंद ने अपने फतवे में इसे रिश्वत और नाजायज करार दिया है। जब मुस्लिम धर्म मे यह नाजायज है तो अन्य धर्म के चिकित्सकों के लिए भी नाजायज ही माना जाएगा। लेकिन वर्तमान में भारी भरकम वेतन व परामर्श फीस लेने पर भी चिकित्सको द्वारा पैथोलॉजी लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड व सिटी स्कैन सेंटरों से मरीज भेजने के नाम पर मोटा कमीशन लेने की शिकायतें आम हो गई है, जिसमे बेचारा मरीज पीस रहा है। ऐसे में इन चिकित्सको को स्वास्थ्य का भगवान कैसे कहे आप ही बताइए।

(लेखक ज्वलंत मुद्दों के जानकार उपभोक्ता कानून के वरिष्ठ अधिवक्ता है)

अंकिता भंडारी हत्याकांड सीबीआई जांच

पूर्ण न्याय की ओर सीएम धामी का फैसला

अंकिता भंडारी केस में राजनीतिक जंग के बीच सीएम धामी की सीबीआई पहल

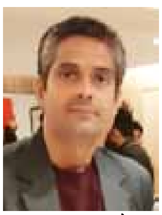

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

तीन साल बाद अंकिता भंडारी का मामला फिर से राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया है। उत्तराखंड की बेटी के न्याय की मांग ने संवेदनाओं और राजनीति दोनों को झकझोरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच के लिए सीबीआई की संस्तुति दी, लेकिन विपक्ष इसे अपर्याप्त मानते हुए शांत नहीं हो रहा है और लगातार सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है। 4 जनवरी को राजधानी देहरादून के घंटाघर में विपक्षी दलों और तमाम छोटे-बड़े सामाजिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ जोरदार रैली और प्रदर्शन किया, जिसमें सीबीआई जांच और वीआईपी संरक्षण को लेकर सवाल उठाए गए। प्रदर्शन के बाद विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि अंकिता भंडारी के मामले में न्याय की मांग पूरी नहीं होने तक वह पीछे नहीं हटेगा। वहीं देहरादून के वसंत विहार थाने में अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पद्मभूषण पर्यावरणविद डॉ. अनिल प्रकाश जोशी की शिकायत के आधार पर की गई है। डॉ. जोशी ने इस संबंध में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक को लिखित शिकायत दी थी, जिसकी जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। दर्ज मुकदमे का उद्देश्य हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराना है। इसी कड़ी में रविवार, 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का एलान किया गया है, जो राज्य में बढ़ते राजनीतिक तनाव और सामाजिक आक्रोश का संकेत माना जा रहा है। अंकिता भंडारी मामला अब सिर्फ एक हत्या का केस नहीं रह गया है, बल्कि यह राज्य सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही की परीक्षा भी बन गया है। विपक्ष के लगातार सड़कों पर सक्रिय रहने से स्पष्ट है कि यह मुद्दा न केवल न्याय की मांग का प्रतीक है, बल्कि राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करने वाला है।

तीन वर्ष पहले पौड़ी जिले में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या का मामला एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत, सामाजिक चेतना और प्रशासनिक जवाबदेही के केंद्र में आ खड़ा हुआ है। अंकिता भंडारी की मौत ने उस समय जिस तरह राज्य को झकझोरा था, वैसी ही हलचल अब दोबारा महसूस की जा रही है। समय बीतने के साथ यह प्रकरण भले ही अदालत की प्रक्रिया में आगे बढ़ा हो, लेकिन न्याय को लेकर उठते सवाल और भावनात्मक आक्रोश पूरी तरह शांत नहीं हो सका। अब जब यह मुद्दा फिर से जनआंदोलन और राजनीतिक बहस का विषय बना है, तो इसका असर राजधानी से लेकर गांवों तक साफ नजर आने लगा है। जनवरी के पहले सप्ताह में देहरादून का घंटाघर इलाका एक बार फिर विरोध का प्रतीक बन गया। अलग-अलग विचारधाराओं से जुड़ी पार्टियों, सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। रैली के दौरान हाथों में तख्तियां, नारों की गूंज और न्याय की मांग ने माहौल को भावुक बना दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इतने लंबे समय बाद भी कई अहम सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। विशेष रूप से कथित प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका और पूरे घटनाक्रम में जिम्मेदारी तय करने को लेकर

संदेह लगातार बना हुआ है। बढ़ते जनदबाव के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से लौटते ही मीडिया के सामने आए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार इस प्रकरण को गंभीरता से ले रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी क्रम में केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की संस्तुति की घोषणा की गई। इस फैसले को सरकार ने पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि राज्य की बेटी को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है और प्रक्रिया में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने दिवंगत अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। इस भेंट को मानवीय पहल के रूप में देखा गया, जहां परिवार के दर्द को समझने और भरोसा दिलाने की कोशिश की गई।
सरकार की ओर से यह संदेश दिया गया कि जांच एजेंसी के जरिए पूरे मामले की गहराई से पड़ताल होगी। हालांकि, यह पहल भी विरोध की आवाजों को पूरी तरह थाम नहीं सकी। विपक्षी दलों का तर्क रहा कि केवल संस्तुति भर से सवाल खत्म नहीं होते, बल्कि जवाबदेही तय करना और समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है। राजनीतिक दलों के साथ-साथ कई सामाजिक मंच भी इस मुद्दे पर सक्रिय हो गए हैं। उनका मानना है कि यह मामला केवल एक परिवार की पीड़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता से जुड़ा है।
आंदोलनों के दौरान बार-बार यह बात उठाई गई कि यदि शुरुआत में ही निष्पक्ष और कठोर कदम उठाए गए होते, तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। इसी सोच के चलते विरोध का दायरा लगातार बढ़ता गया। चार जनवरी को हुए प्रदर्शन के बाद विपक्षी खेमे ने साफ संकेत दे दिए थे कि आंदोलन यहीं थमने वाला नहीं है। कई बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं के बाद रविवार, 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का एलान किया गया। इस आहवान में विभिन्न दलों के अलावा छोटे राजनीतिक समूह, छात्र संगठन और नागरिक मंच भी शामिल हो गए।
बंद के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जांच प्रक्रिया पर लगातार निगरानी बनी रहे और किसी भी स्तर पर समझौते की गुंजाइश न रहे। राज्य में इस तरह का बंद लंबे अंतराल के बाद देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती, यातायात व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश और आवश्यक सेवाओं को सुचारु रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, सरकार की ओर से यह अपील भी की गई है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे और आम लोगों को परेशानी न हो। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या न्याय की प्रक्रिया केवल कानूनी दायरे में सिमट कर रह जानी चाहिए, या फिर समाज की संवेदनाओं को भी उतनी ही अहमियत

अंकिता हत्याकांड पर सियासी संग्राम, सीबीआई जांच को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने

अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति किए जाने के बावजूद राज्य की राजनीति में उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां भाजपा इस फैसले को जनभावनाओं के अनुरूप बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे नाकाफी करार देते हुए सरकार की मंशा और जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सीबीआई जांच से विपक्ष के झूठ और दुष्प्रचार का पर्दाफाश होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरुआत से ही इस मामले में गंभीरता दिखाई है और अंकिता के हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। मामले की निष्पक्ष जांच कराई गई और अब पीड़ित परिवार की भावना का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है, ताकि किसी भी प्रकार का संदेह शेष न रहे। महेंद्र भट्ट ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि अंकिता प्रकरण पर शुरू से ही राजनीति की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने किसी दबाव में नहीं बल्कि जनभावनाओं और पीड़ित परिवार की इच्छा को देखते हुए यह फैसला लिया है। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज का नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर किए जाने को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को राजनीतिक झूठ बताया और कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही शासनादेश जारी कर दिया गया था, इसके बावजूद भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के नाम पर समाज को बांटने और माहौल खराब करने की कोशिशों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और संगठनों से अपील की कि इस संवेदनशील मामले पर राजनीति बंद की जाए और न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित न किया जाए। भट्ट ने अफसोस जताते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के लिए अंकिता की मौत सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गई है, जबकि न तो उन्हें पीड़ित परिवार की राय की परवाह है और न ही किसी संस्थान के नामकरण के महत्व की। दूसरी ओर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीबीआई जांच के आदेश को अपर्याप्त बताया है। उन्होंने कहा कि यह देवभूमि की जागरूक जनता की जीत जरूर है, लेकिन यह जीत अभी अधूरी है। गोदियाल ने सवाल उठाया कि जब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो सीबीआई की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर संदेह स्वाभाविक है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिन लोगों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, वे प्रभावशाली पदों पर बैठे हैं और सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं। ऐसे में केवल सीबीआई जांच का आदेश जनता की आशंकाओं को दूर नहीं करता। उन्होंने कहा कि यह मामला इतना संवेदनशील और गंभीर है कि इसकी जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए थी, तभी सच्चाई पूरी तरह सामने आ सकती है। गणेश गोदियाल ने यह भी आरोप लगाया कि सीबीआई जांच की संस्तुति देकर धामी सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि अतीत में इस मामले में बड़ी चूक हुई है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि सरकार अब अपनी गलती सुधारने का प्रयास कर रही है, लेकिन यह प्रयास अभी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने साफ किया कि जब तक अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का खुलासा नहीं हो जाता, जब तक बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े अधिकारियों के नाम सामने नहीं आते और उन्हें सजा नहीं मिलती, तब तक कांग्रेस का आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जारी यह राजनीतिक टकराव साफ तौर पर दिखा रहा है कि मामला केवल जांच तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह राज्य की राजनीति का बड़ा केंद्र बिंदु बन चुका है, जहां हर फैसला और बयान सियासी नजरिए से तौला जा रहा है।

मिलनी चाहिए। अंकिता भंडारी का नाम अब केवल एक व्यक्ति की पहचान नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है, जो सत्ता, व्यवस्था और जवाबदेही के बीच संतुलन की मांग करता है। यही वजह है कि तीन साल बाद भी यह प्रकरण लोगों की भावनाओं को छू रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने के अवसर के रूप में देख रहा है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन पूरी तरह निष्पक्ष होता, तो इतने लंबे समय तक आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी ओर, सत्तापक्ष का तर्क है कि जांच को प्रभावित किए बिना उसे सही दिशा में ले जाना जरूरी है और राजनीतिक दबाव से प्रक्रिया कमजोर हो सकती है। इन दोनों पक्षों के बीच चल रही बयानबाजी ने माहौल को और गर्म कर दिया है। मीडिया और सामाजिक मंचों पर भी इस मामले को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। देशभर में यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रभाव और रसूख के आगे न्याय कमजोर पड़ता है, या फिर अंततः सच्चाई सामने आती है। यही कारण है कि यह प्रकरण अब केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन गया है। वहीं देहरादून के वसंत विहार थाने में अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पद्मभूषण पर्यावरणविद डॉ. अनिल प्रकाश जोशी की शिकायत के आधार पर की गई है। डॉ. जोशी ने इस संबंध में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक को लिखित शिकायत दी थी, जिसकी जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। दर्ज मुकदमे का उद्देश्य हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराना है। डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन इंटरनेट मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं में यह आशंका जताई जा रही है कि कुछ अहम साक्ष्यों को छिपाया या नष्ट किया गया। उन्होंने कहा कि मामले में एक अज्ञात वीआईपी व्यक्ति की संलिप्तता को लेकर गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, जिसकी अलग से जांच आवश्यक है। डॉ. जोशी का कहना था कि यह कथित वीआईपी से जुड़ा एक स्वतंत्र अपराध हो सकता है, इसलिए पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस पहलू की पृथक और निष्पक्ष जांच जरूरी है। आने वाले दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसी की भूमिका पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। जांच की दिशा, निष्कर्ष और आगे की कानूनी प्रक्रिया यह तय करेगी कि जनता का भरोसा किस हद तक बहाल हो पाता है। फिलहाल इतना तय है कि अंकिता भंडारी का मामला एक बार फिर राज्य की राजनीति, समाज और प्रशासन के लिए परीक्षा बन चुका है, जहां हर कदम पर पारदर्शिता और संवेदनशीलता की अपेक्षा की जा रही है।

दून उद्योग व्यापार मंडल बाजार बंद करने के आव्हान से हुआ अलग

दून उद्योग व्यापार मंडल ने प्रस्तावित उत्तराखंड बंद से खुद को अलग रखते हुए स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति और विधिक कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद बंद का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मंडल ने इसे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने वाला और राजनीति से प्रेरित आहवान बताया है। इस संबंध में दून उद्योग व्यापार मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 11 जनवरी के बंद में मंडल की कोई भी इकाई शामिल नहीं होगी। बैठक में कहा गया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है और पीड़ित परिवार की मांग पर सीबीआई जांच की संस्तुति भी हो चुकी है। ऐसे में बंद का आहवान अनावश्यक है।

व्यापार मंडल ने यह भी आरोप लगाया कि किसी भी संगठन ने बंद के समर्थन के लिए न तो उनसे संपर्क किया और न ही सहमति ली। केवल एकतरफा घोषणा कर व्यापारियों को डराने की कोशिश की जा रही है। मंडल ने चेतावनी दी कि यदि किसी व्यापारी के साथ जबरदस्ती या छेड़छाड़ की गई तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर एसएसपी से संपर्क कर आवश्यक कदम उठाने की मांग की जाएगी। दून उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन नागलिया ने व्यापारियों से अपील की कि वे बंद के झांसे में न आएं और अपने प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खोलें। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में राज्य सरकार ने शुरुआत से ही त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया था और दोषियों को सजा दिलाई गई। बाद में सामाजिक और राजनीतिक दबाव के बीच मुख्यमंत्री ने पीड़ित माता-पिता से मुलाकात कर सीबीआई जांच की संस्तुति भी दे दी। ऐसे में बंद का कोई औचित्य नहीं है और रविवार को भी बाजार सामान्य रूप से संचालित होंगे। महासचिव सुनील मैंसन ने कहा कि दून उद्योग व्यापार मंडल का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने दोहराया कि अंकिता भंडारी मामले में सभी आरोपी जेल में हैं और सीबीआई जांच की मांग को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए देहरादून के सभी बाजार, संडे बाजार सहित, नियमानुसार खुले रहेंगे और व्यापार सामान्य रूप से जारी रहेगा। मंडल ने प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिशों से बचने की अपील करते हुए कहा कि व्यापारी वर्ग हमेशा प्रदेश हित में खड़ा रहा है और अनावश्यक आंदोलनों के नाम पर व्यापार बंद कराना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

धामी सरकार ने राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ पौड़ी का नाम अंकिता भंडारी रखा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जनपद स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ (श्रीकोट) का नाम अब 'स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ (श्रीकोट), पौड़ी' रखा गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के तुरंत बाद इस फैसले पर अमल करते हुए शासनादेश जारी कर दिया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार द्वारा गुरुवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया गया, जिससे यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह फैसला केवल एक नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की स्मृति को सम्मान देने और उसके साथ हुए अन्याय के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाने वाला कदम माना जा रहा है। तीन साल बाद भी अंकिता का नाम राज्य और देश की चेतना में जीवित है और न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे में एक शैक्षणिक संस्थान का नाम उसके नाम पर किया जाना उस पीड़ा और संघर्ष को स्थायी पहचान देने जैसा है, जिसे प्रदेश कभी भुला नहीं सकता। इससे

अंकिता भंडारी केस में अब तक की प्रमुख घटनाएं

18 सितंबर 2020 को वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की शुरुआती सुस्ती के चलते मामला सोशल मीडिया पर उछल गया, जिससे सरकार और पुलिस पर दबाव बढ़ा। 23 सितंबर 2022 को पुलिस ने अंकिता भंडारी की हत्या के आरोप में वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता और मैनेजर सौरभ भास्कर को गिरफ्तार किया। 24 सितंबर 2022 को पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि अंकिता की हत्या कर शव को चीला बैराज में धकेला गया था। दो दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बैराज से अंकिता का शव बरामद किया गया। 30 मई 2025 को कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को उम्रकैद की सजा सुनाई। 22 दिसंबर 2025 को एक्ट्रेस उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मामला दोबारा गरमा गया। 7 जनवरी 2026 को अंकिता भंडारी के माता-पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग रखी। 9 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की औपचारिक घोषणा की। तीन साल बाद एक बार फिर अंकिता भंडारी का मामला न्याय, राजनीति और व्यवस्था की कसौटी बन गया है। अब सभी की निगाहें सीबीआई जांच पर टिकी हैं, जिससे इस बहुचर्चित हत्याकांड से जुड़े हर सवाल का जवाब सामने आने की उम्मीद की जा रही है।

एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार के दु:ख को गंभीरता से सुना और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पीड़ित परिवार द्वारा रखी गई प्रत्येक मांग पर विधि-सम्मत, निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाना केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सरकार की सर्वोच्च नैतिक प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरा मामला पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। नर्सिंग कॉलेज का नामकरण उसी भरोसे और संवेदनशीलता की कड़ी माना जा रहा है, जिसके माध्यम से सरकार यह संदेश देना चाहती है कि अंकिता केवल एक केस फाइल नहीं, बल्कि प्रदेश की बेटी है। राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर किए जाने से न केवल पौड़ी जनपद, बल्कि पूरे उत्तराखंड में भावनात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े इस संस्थान के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां अंकिता के नाम और उसकी कहानी से जुड़ेंगी, जो समाज को संवेदनशील, जागरूक और जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक प्रतीकात्मक पहल मानी जा रही है। सरकार का यह निर्णय ऐसे समय आया है, जब अंकिता भंडारी का मामला एक बार फिर सियासी और सामाजिक विमर्श के केंद्र में है। ऐसे में यह कदम प्रशासनिक निर्णय से आगे बढ़कर एक भावनात्मक और सामाजिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि राज्य अपनी बेटियों की स्मृति और सम्मान के साथ खड़ा है और न्याय की लड़ाई में पीछे हटने वाला नहीं है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला पहली बार 22 सितंबर 2022 को सामने आया था

अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। यह मामला पहली बार 22 सितंबर 2022 को सामने आया था, जब पौड़ी जिले के लक्ष्मणझूला क्षेत्र स्थित वनंतरा रिजॉर्ट से जुड़ी इस सनसनीखेज घटना ने राज्य की राजनीति और प्रशासन को झकझोर दिया था। जिलाधिकारी के आदेश पर लक्ष्मण झूला थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और शुरुआती दबाव के बीच धामी सरकार ने 24 सितंबर 2022 को जांच के लिए विशेष जांच टीम का गठन किया था। जांच के दौरान तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी। सरकार की ओर से इसे न्यायिक प्रक्रिया की बड़ी सफलता बताया गया, लेकिन समय बीतने के साथ यह मामला पूरी तरह शांत नहीं हो सका। हाल के दिनों में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी दूसरी पत्नी, एक्ट्रेस उर्मिला सनावर की कथित कॉल रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद यह प्रकरण एक बार फिर सियासी तूफान के केंद्र में आ गया। वायरल ऑडियो में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का जिक्र किए जाने और कथित वीआईपी गेस्ट को लेकर अंकिता की हत्या की बात सामने आने से विपक्षी कांग्रेस को बड़ा मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने इसे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार और भाजपा को घेरने का हथियार बना लिया। इसके बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई और सरकार पर दोबारा जांच कराने का दबाव बढ़ने लगा। बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की। परिवार की भावनाओं और मांगों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अंतत: मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया। माना जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से कथित वीआईपी गेस्ट को लेकर चल रही चर्चाओं पर से पर्दा उठ सकता है और पूरे मामले की गहराई से जांच हो सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि अंकिता भंडारी केस में सरकार का उद्देश्य शुरू से ही निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना रहा है और आगे भी यही प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार को इस मामले की जानकारी मिली थी, बिना किसी विलंब के कार्रवाई की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार आगे भी न्याय प्रक्रिया को मजबूती से आगे बढ़ाएगी।

उद्यमिता और नेतृत्व में महिला शक्ति का निर्णायक उदय

महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व और उद्यमिता को केंद्र में रखते हुए देहरादून में डॉ. गीता खन्ना के नेतृत्व में एक गरिमामय एवं प्रेरणादायी दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जिसमें महिलाओं की भूमिका को सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय विकास की मजबूत आधारशिला के रूप में रेखांकित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित इस सम्मेलन में देश और राज्य स्तर के नीति-निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, महिला उद्यमियों, विशेषज्ञों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने सहभागिता की। सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें उद्यमिता, डिजिटल जागरूकता, नवाचार, सतत आजीविका और नेतृत्व के अवसरों से जोड़ना रहा, ताकि महिलाएं न केवल अपने लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के समग्र विकास में निर्णायक भूमिका निभा सकें। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार ने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना देश का समग्र विकास संभव नहीं है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और गणेश जोशी ने अपने संबोधनों में महिला उद्यमिता, स्वरोजगार और नेतृत्व क्षमता को राज्य और देश के विकास का आधार बताते हुए ऐसे मंचों को महिलाओं के लिए मार्गदर्शक और प्रेरक बताया। सम्मेलन में सरकारी योजनाओं, डिजिटल जागरूकता, साइबर सुरक्षा, जैविक खेती, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के लिए नए अवसरों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट)

महिला नेतृत्व, उद्यमिता और सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 7 जनवरी को एक भव्य एवं प्रेरणादायी दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड उद्योग परिसंघ महिला संगठन के उत्तराखंड प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में महिलाओं की भूमिका को सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय विकास की मजबूत आधारशिला के रूप में रेखांकित किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार किसी अपरिहार्य कारणवश कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता और विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की निर्णायक भूमिका पर जोर दिया। दो दिवसीय इस सम्मेलन की विषयवस्तु महिलाओं को सशक्त बनाने की शक्ति पर आधारित रखी गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण, उद्यम विकास, सरकारी सहभागिता और सतत आजीविका के अवसरों से जोड़ना है। सम्मेलन के पहले दिन की शुरुआत भव्य उद्घाटन सत्र से हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विशेष अतिथि के रूप में सहभागिता की। उन्होंने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण, नव उद्यमों की संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महिलाओं की निर्णायक भूमिका पर विस्तार से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं उद्यमिता से जुड़ती हैं, तो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को नई दिशा मिलती है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने वक्तव्य में कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं सदैव समाज और विकास की अग्रणी रही हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को राज्य के समग्र विकास की आधारशिला बताते हुए कहा कि ऐसे मंच महिलाओं की प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस अवसर पर उत्तराखंड उद्योग परिसंघ महिला संगठन की उत्तराखंड प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि महिला उद्यमिता राज्य और देश के आर्थिक विकास की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने की यह पहल केवल एक विषय नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर, सक्षम और नेतृत्वकर्ता बनाने की दिशा में एक सशक्त आंदोलन है। उन्होंने यह भी कहा कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो परिवार, समाज और राष्ट्र स्वतः सशक्त होता है। सम्मेलन के दौरान साइबर जागरूकता विषय पर आयोजित सत्र में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंकुश मिश्रा ने साइबर अपराधों से बचाव, डिजिटल सुरक्षा और सतर्कता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा कीं। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय सजग और सुरक्षित रहें। इसके साथ ही व्यवसाय और विपणन क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर केंद्रित सत्र में विशेषज्ञ जूही खन्ना और करिश्मा डिंगरा ने आधुनिक तकनीक के माध्यम से व्यवसाय को सशक्त बनाने के व्यावहारिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विषय विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा का आयोजन भी किया गया। सम्मेलन में उत्तराखंड में जैविक खेती, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों की व्यापक संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि ये क्षेत्र महिला उद्यमियों के लिए आजीविका सृजन और आर्थिक समृद्धि के बड़े अवसर प्रदान कर सकते हैं। पैनल चर्चा में महिला सहभागिता और सतत विकास पर विशेष बल दिया गया। इस अवसर पर डॉ. सुरेखा डंगवाल, श्रीमती मधु भट्ट, श्रीमती कुसुम कंडवाल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने महिलाओं को विशिष्ट पहचान दिलाने और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को और अधिक सशक्त करने पर जोर दिया।

महिलाओं के संकल्प और सामूहिक शक्ति से समाज और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है

महिलाओं की सोच, संकल्प और सामूहिक शक्ति जब एक मंच पर एकत्र होती है, तो केवल विचार नहीं जन्म लेते, बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। इसी भावनात्मक और प्रेरणादायी वातावरण में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित दो दिवसीय महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता सम्मेलन का द्वितीय सत्र 8 जनवरी को अत्यंत उत्साह, सार्थक संवाद और प्रेरक विचार-विमर्श के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि महिलाएं केवल परिवर्तन की सहभागी नहीं, बल्कि परिवर्तन की सूत्रधार हैं। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल की धर्मपत्नी एवं प्रथम महिला द्वारा भेजे गए वीडियो संदेश का प्रसारण किया गया, जिसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास और सतत प्रगति के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए सम्मेलन की सफलता हेतु शुभकामनाएं दीं।

उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि श्रीमती गीता धामी ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा कि जब महिलाएं आत्मविश्वास, संकल्प और निरंतर परिश्रम के साथ आगे बढ़ती हैं, तो वे न केवल स्वयं को सशक्त बनाती हैं, बल्कि पूरे समाज को नई दिशा देती हैं। उन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं से आहवान किया कि वे राज्य और देश का नाम रोशन करते हुए अपनी अलग पहचान स्थापित करें। इसके पश्चात "संकल्प से सिद्धि तक" विषय पर आयोजित सत्र में सुश्री नेहा जोशी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर प्रयास और आत्मबल के सहारे महिलाएं किसी भी क्षेत्र में सफलता की नई इबारत लिख सकती हैं। जलवायु परिवर्तन विषयक तकनीकी सत्र में आयोजित कार्यशाला में यह बताया गया कि दैनिक जीवन में अपनाए गए छोटे-छोटे निर्णय और व्यवसाय में सतत उपाय किस प्रकार पर्यावरण के अनुकूल भविष्य के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने जीवनशैली और व्यापार में जिम्मेदार व्यवहार को आवश्यक बताया। वित्तीय साक्षरता से जुड़े सत्र में महिलाओं को आर्थिक नियोजन, बचत, निवेश और आत्मनिर्भरता के व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल ने कहा कि सुदृढ़ वित्तीय समझ किसी भी व्यवसाय और संगठन की सफलता की आधारशिला होती है। कार्यक्रम में प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट ने महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने और निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं राज्य मंत्री (श्रम विभाग) श्रीमती गीता रावत ने श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और अधिकारों पर अपने विचार साझा किए। इसके उपरांत महिला उद्यमिता में स्थिरता विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में विशेषज्ञों ने इस बात पर बल दिया कि यदि व्यापार के केंद्र में स्थिरता को रखा जाए, तो दीर्घकालीन सफलता के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन भी सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती लुबना ने संगठन से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस मंच ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने महिलाओं से निरंतर सीखते रहने और आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। सम्मेलन की सफलता में आयोजन समिति और कार्यकारिणी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोमल बत्रा, नेहा शर्मा, त्रिप्ती बहल, मीनाक्षी सोती, स्मृति बट्टा एवं हरप्रीत कौर की सक्रिय सहभागिता और कुशल प्रबंधन की विशेष रूप से सराहना की गई। अंतिम सत्र में महिलाओं के नेतृत्व में सतत विकास विषय पर गहन चर्चा हुई, जिसमें विशेषज्ञों और विशिष्ट अतिथियों ने व्यापार में पर्यावरणीय और सामाजिक उत्तरदायित्व को आत्मसात करने पर बल दिया। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि जब महिलाएँ स्थिरता को केंद्र में रखकर कार्य करती हैं, तो समाज और प्रकृति दोनों के लिए सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। कार्यक्रम का समापन समापन सत्र के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए और सम्मेलन की समग्र उपलब्धियों को साझा किया गया। कुल मिलाकर सम्मेलन का द्वितीय दिवस महिला नेतृत्व, वित्तीय सशक्तिकरण और जिम्मेदार उद्यमिता की दिशा में एक सशक्त और प्रेरणादायी पहल के रूप में यादगार बन गया।

हरीश चंद्र अंडोला उत्कृष्ट लेखन कार्यों के लिए सम्मानित

दून विश्वविद्यालय के डॉ. हरीश चंद्र अंडोला को उनके द्वारा उत्कृष्ट लेखन के कार्यों के लिए सोच संस्था द्वारा उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉ. हरीश चंद्र अंडोला द्वारा दून यूनिवर्सिटी के कुलपति, कुलसचिव तथा पर्यावरण विभाग के प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं समस्त छात्र छात्राओं तथा कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष प्रोफे. देवेंद्र भसीन, पूर्व राजपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व सलाहकार रूसा प्रोफे. एम. एस. एम. रावत जी, प्रोफे. के. डी. पुरोहित, प्रोफे. विपिन चंद्र जोशी, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा प्रोफे. आनंद सिंह उनियाल, उप निदेशिका डॉ. ममता नैथानी, डॉ. विपिन चंद्र चौबे, प्रोफे. विजयकान्त पुरोहित, डायरेक्टर जनरल यूकॉस्ट श्री दुर्गेश पंत, पूर्व कुलपति प्रो सोबन सिंह जीना, आईआईसीएआर के सीनियर साइंटिस्ट डॉ वीरेन्द्र सिंह राणा जी, भारतीय वन सेवा के डॉ चन्द्र शेखर सनवाल, प्रो एम. एस. पुरोहित के मार्गदर्शन देवभूमि विचार मंच के श्री कैलाश अंडोला, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री के आर भट्ट जी, डॉ. बृजेश बनकोटी जी, निदेशक, जी. बी. पंत संस्थान कोसी, अल्मोड़ा का आभार व्यक्त किया गया। युगबाणी के मुख्य संवाददाता श्री जगमोहन रौतेला, डॉ शैलेश उप्रेती, डॉ. विक्रम डोबाल, डॉ नवीन जोशी, भारतीय सिविल सेवा आईएएस के पूर्णेश गुरुरानी, डॉ प्रशांत दुर्गापाल, एम्स ऋषिकेस गोपाल बिष्ट जी प्रशांत मेहता कुनाल पब्लिकेशन के प्रकाशक श्री प्रेम सिंह बिष्ट तथा कर्मचारियों के सहयोग के लिए हेम पंत जी दयाल पाण्डेय मेरा पहड मेरी पहचान के आभार व्यक्त किया।

साइबर फ्रॉड एक चुनौती, सजगता है जरूरी

मनोज श्रीवास्तव
उपनिदेशक, प्रभारी विधान सभा मीडिया सेंटर, देहरादून

आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन थोड़ी-सी लापरवाही से व्यक्ति आर्थिक नुकसान, पहचान की चोरी, ब्लैकमेलिंग या मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो सकता है। इसलिए साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है।

सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है सोशल मीडिया ऐप या अकाउंट में टू-स्टेप वेरिफिकेशन का उपयोग। विशेष रूप से व्हाट्सएप, फेसबुक, ई-मेल और बैंकिंग ऐप्स में यह सुविधा अवश्य सक्रिय होनी चाहिए। टू-स्टेप वेरिफिकेशन में पासवर्ड के साथ-साथ एक अतिरिक्त कोड या पिन की आवश्यकता होती है, जिससे यदि पासवर्ड किसी तरह लीक भी हो जाए, तब भी अकाउंट सुरक्षित रहता है। व्हाट्सएप पर 6 अंकों का पिन लगाकर अकाउंट हैक होने की संभावना काफी कम हो जाती है।

दूसरी महत्वपूर्ण सावधानी है ई-मेल और डिवाइस की सुरक्षा। अपना ई-मेल किसी साइबर कैफे, होटल, दोस्त के मोबाइल या सार्वजनिक कंप्यूटर पर लॉग-इन करके कभी भी खुला न छोड़ें। उपयोग के बाद तुरंत लॉग-आउट करें। यदि पुराना मोबाइल किसी को देना हो, तो पहले उसे पूरी तरह फॉर्मेट करें और उसमें से सभी ई-मेल, सोशल मीडिया, बैंकिंग ऐप्स और डाटा हटा दें। अपना पर्सनल लैपटॉप या मोबाइल किसी अनजान व्यक्ति को न दें, क्योंकि इनमें आपकी निजी और संवेदनशील जानकारी होती है।

तीसरी सावधानी है आधार कार्ड की सुरक्षा। आजकल कई जगह पहचान के लिए आधार मांगा जाता है। ऐसी स्थिति में पूरा आधार कार्ड देने के बजाय केवल मास्क्ड आधार ही दें, जिसमें अंतिम के केवल चार अंक दिखाई देते हैं। यह मास्क्ड आधार युआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। पूरा आधार साझा करने से पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है।

चौथी सावधानी सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी सीमित रखना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने घर का पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, बच्चों की जानकारी, यात्रा की योजना या आर्थिक स्थिति जैसी जानकारियाँ सार्वजनिक न करें। अपनी फ्रेंड लिस्ट को ''ऑनली मी'' या ''फ्रेंडस'' तक सीमित रखें, ताकि अनजान लोग आपकी प्रोफाइल का गलत इस्तेमाल न कर सकें। फर्जी प्रोफाइल और अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट से विशेष सावधानी बरतें।

पाँचवां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि साइबर फ्रॉड का मुख्य कारण लालच, भय और सोशल मीडिया पर अंधविश्वास होता है। "लॉटरी लग गई", "इनाम जीता", "बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा", "तुरंत लिंक खोलें" जैसे मैसेज अक्सर धोखाधड़ी के लिए भेजे जाते हैं। ऐसे मैसेज, कॉल या ई-मेल पर बिना जांच-पड़ताल के विश्वास न करें। सोशल मीडिया और इंटरनेट को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए।

छठी और अत्यंत आवश्यक सावधानी है यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी सुरक्षा। यदि आपके खाते में किसी अनजान व्यक्ति से अचानक पैसे आ जाएँ, तो तुरंत बैलेंस चेक करने के लिए यूपीआई पिन न डालें। कई बार साइबर अपराधी नकली रिक्वेस्ट या लिंक के माध्यम से पिन डलवाकर अकाउंट खाली कर देते हैं। अनजान पेमेंट आने पर बैंक या कस्टमर केयर से संपर्क करें। कभी भी किसी को यूपीआई पिन, ओटीपी या कार्ड डिटेल न बताएं।

सातवा यदि आपने यूपीआई से गलत पेमेंट कर दिया है तो आरबीआई के टोल फ्री नम्बर-18001201740 पर 48 घंटे के अन्दर कॉल कर लें और गूगल पर एनपीआई वेबसाइट पर यूपीआई के शिकायत दर्ज कर लें।

आठवां सरकारी ऐप संचार साथी को डाउनलोड कर लें इसे फोन का पहरेदार कहते है। इसके माध्यम से साइबर फ्रॉड का शिकायत दर्ज कर सकते है, फोन चोरी होने पर रिर्पोट दर्ज कर सकते है।

नवां MOBI ARMOUR ऐप साइबर फ्रॉड बचाने में मदद करता है। संदेहास्पद लिंक और बारकोड को चेक किया जा सकता है।इसके अतिरिक्त, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, जिसमें अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल हों। एक ही पासवर्ड सभी ऐप्स में न रखें। समय-समय पर पासवर्ड बदलते रहें। अनजान लिंक, फाइल या क्यूआर कोड स्कैन करने से बचें। मोबाइल और कंप्यूटर में एंटी-वायरस और सॉफ्टवेयर अपडेट रखें।

अंत में यही कहा जा सकता है कि साइबर क्राइम से बचाव का सबसे बड़ा हथियार जागरूकता और सतर्कता है। थोड़ी-सी सावधानी हमें बड़े नुकसान से बचा सकती है। डिजिटल सुविधाओं का उपयोग करें, लेकिन समझदारी और सुरक्षा के साथ।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 108 आपातकालीन सेवा बनी उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत ढाल

"गोल्डन हावर" में त्वरित उपचार से जीवन रक्षा, 108 आपातकालीन सेवा पाँच वर्षों में तकनीक, तत्परता और मानवीय संवेदना का सशक्त उदाहरण

उत्तराखंड सरकार के लिए नागरिकों का जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के सतत मार्गदर्शन में राज्य की 108 आपातकालीन सेवा ने बीते पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान आपात स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक सशक्त, भरोसेमंद और प्रभावी प्रणाली के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। पर्वतीय, दुर्गम और मौसम की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड जैसे राज्य में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है, किंतु 108 सेवा ने प्रशासनिक प्रतिबद्धता, तकनीकी नवाचार और प्रशिक्षित मानव संसाधन के बल पर इस चुनौती को अवसर में बदला है। यह प्रेस नोट 108 आपातकालीन सेवा की पाँच-वर्षीय यात्रा, उपलब्धियों, आँकड़ों, सुधारों और भविष्य की दिशा का विस्तृत एवं तथ्यपरक विवरण प्रस्तुत करता है।

संकट की घड़ी में जीवनरेखा: 108 आपातकालीन सेवा राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए आपदा और संकट की घड़ी में जीवनरेखा के समान है। सड़क दुर्घटनाएँ, हृदयाघात, प्रसव संबंधी आपात स्थितियाँ, गंभीर बीमारियाँ, प्राकृतिक आपदाएँ अथवा भीड़भाड़ वाले धार्मिक व राष्ट्रीय आयोजन-हर परिस्थिति में यह सेवा 24×7 तत्परता के साथ सक्रिय रहती है। बीते पाँच वर्षों में 108 सेवा का उद्देश्य केवल मरीज को अस्पताल तक पहुँचाना भर नहीं रहा, बल्कि "गोल्डन ऑवर" के भीतर गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराकर जीवन रक्षा सुनिश्चित करना इसकी कार्यसंस्कृति का मूल आधार बना है।

पाँच वर्षों में आपात मामलों का विस्तृत विश्लेषण: पिछले पाँच वर्षों में 108 आपातकालीन सेवा ने यह सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, सक्षम प्रशासन और आधुनिक तकनीक के समन्वय से किसी भी चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में भी विश्वस्तरीय आपात स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है। उत्तराखंड सरकार नागरिकों के जीवन की रक्षा हेतु इस सेवा को निरंतर सशक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। पाँच वर्षों के आँकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि 108 आपातकालीन सेवा ने समय के साथ न केवल कार्यभार संभाला, बल्कि हर वर्ष अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया।

कोविड काल की चुनौती और सेवा की परीक्षा: वर्ष 2020-21 में 108 सेवा के अंतर्गत कुल 1,06,768 आपात मामले दर्ज किए गए। यह वह दौर था जब कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर अभूतपूर्व दबाव बना दिया था। सीमित संसाधनों और अत्यधिक मांग के बावजूद 108 सेवा ने निरंतर कार्य करते हुए राज्यभर में आपात स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चित की।

2021-22: मामलों में तेज वृद्धि, जिम्मेदारी में इजाफा: वर्ष 2021-22 में आपात मामलों की संख्या में लगभग 48 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और यह आँकड़ा 1,58,070 तक पहुँच गया। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर, गंभीर मरीजों की संख्या में वृद्धि, ऑक्सीजन सपोर्ट और अस्पताल रेफरल की बढ़ी मांग ने 108 सेवा की कार्यक्षमता की वास्तविक परीक्षा ली, जिसमें सेवा पूरी तरह सफल रही।

2022-23: सर्वाधिक मामलों का वर्ष: वर्ष 2022-23 में 1,62,301 आपात मामलों के साथ पाँच वर्षों का सर्वाधिक आंकड़ा दर्ज हुआ। महामारी के बाद उत्पन्न जटिल स्वास्थ्य स्थितियों, पुरानी बीमारियों के गंभीर मामलों और सामान्य आपात स्थितियों को 108 सेवा ने समान दक्षता से संभाला।

2023-24 और 2024-25: सकारात्मक गिरावट का संकेत: इसके बाद वर्ष 2023-24 में आपात मामलों की संख्या घटकर 1,51,276 और 2024-25 में 1,38,369 रह गई। यह कमी किसी भी प्रकार की कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों, समय पर प्राथमिक उपचार, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थानों की मजबूती और कॉल ट्रायजिंग प्रणाली की

सफलता को दर्शाती है।

पहाड़ों में सेवा देना, सबसे बड़ी चुनौती: उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में आपात सेवा का सबसे महत्वपूर्ण मानक प्रतिक्रिया समय है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ, सीमित सड़क नेटवर्क और मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद 108 सेवा ने इस दिशा में निरंतर सुधार किए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिक्रिया समय:
2020-21 में औसत प्रतिक्रिया समय: 24.18 मिनट
2021-22 में सुधार के साथ: 20.34 मिनट
2024-25 में औसत प्रतिक्रिया समय: 23.09 मिनट
हाल के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिक्रिया समय में हल्की वृद्धि भौगोलिक कठिनाइयों और लंबी दूरी के कारण देखी गई है, जिस पर सरकार द्वारा निरंतर सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है।

शहरी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन:
2020-21 में: 13.13 मिनट
2021-22 में: 10.18 मिनट
2024-25 में: 12.48 मिनट
शहरी क्षेत्रों में बेहतर सड़क नेटवर्क, तकनीकी संसाधनों और कुशल कॉल प्रबंधन प्रणाली के कारण 108 सेवा की प्रतिक्रिया क्षमता लगातार सुदृढ़ बनी रही है।

कॉल वॉल्यूम और प्रभावी कॉल प्रबंधन प्रणाली: वर्ष 2020-21 में 108 सेवा को कुल 10,11,047 कॉल्स प्राप्त हुई, जो पाँच वर्षों में सर्वाधिक थीं। महामारी के दौरान जानकारी, सहायता और आपात जरूरतों के लिए कॉल्स की संख्या स्वाभाविक रूप से अधिक रही। इसके बाद कॉल्स की संख्या में गिरावट दर्ज की गई, किंतु वर्ष 2024-25 में यह पुनः बढ़कर 8,00,473 तक पहुँच गई। यह नागरिकों में 108 सेवा के प्रति बढ़ते भरोसे और जागरूकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

कॉल ट्रायजिंग और तकनीकी नवाचार: 108 आपातकालीन सेवा में आधुनिक कॉल ट्रायजिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत कॉल्स को उनकी गंभीरता के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। इससे गंभीर मरीजों को तत्काल सहायता उपलब्ध होती है और एंबुलेंस संसाधनों का अधिकतम व न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित होता है। इसके साथ ही जीपीएस आधारित एंबुलेंस ट्रैकिंग, डिजिटल डेटा रिकॉर्डिंग और रियल-टाइम मॉनिटरिंग ने सेवा की पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है।

आपदाओं और बड़े आयोजनों में 108 सेवा की निर्णायक भूमिका: पिछले पाँच वर्षों में 108 सेवा ने अनेक बड़े आयोजनों और आपात अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कोविड-19 महामारी: संक्रमित मरीजों का सुरक्षित परिवहन, ऑक्सीजन सपोर्ट और आपात रेफरल

चारधाम यात्रा: ऊँचाई से संबंधित बीमारियाँ, सड़क दुर्घटनाएँ और त्वरित रेस्क्यू

कुंभ मेला 2021: लाखों श्रद्धालुओं के लिए व्यापक मेडिकल कवरेज

कांवड़ यात्रा: डिहाइड्रेशन, थकान और दुर्घटनाओं में त्वरित चिकित्सा सहायता

जी-20 शिखर सम्मेलन: उच्च स्तरीय मेडिकल रेडीनेस और एडवांस लाइफ सपोर्ट

सिलक्यारा टनल रेस्क्यू: फँसे श्रमिकों को त्वरित चिकित्सा सहायता और सुरक्षित अस्पताल परिवहन

मानव संसाधन, सेवा की असली ताकत
108 सेवा की सफलता के मूल में प्रशिक्षित एंबुलेंस पायलट, ईएमटी, कॉल हैंडलर और तकनीकी स्टाफ की अहम भूमिका है। इन्हें समय-समय पर एडवांस लाइफ सपोर्ट, ट्रॉमा केयर और आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

स्वास्थ्य सचिव का वक्तव्य: इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा 108 आपातकालीन सेवा उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। पिछले पाँच वर्षों के आँकड़े यह प्रमाणित करते हैं कि इस सेवा ने हर चुनौती का सामना मजबूती और संवेदनशीलता के साथ किया है। भविष्य में हमारा फोकस ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में प्रतिक्रिया समय को और बेहतर करने, तकनीकी संसाधनों को अपग्रेड करने तथा मानव संसाधन क्षमता को सशक्त बनाने पर रहेगा। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा राज्य सरकार 108 आपातकालीन सेवा को और अधिक मजबूत, तेज और जन-केन्द्रित बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में नई एंबुलेंसों का समावेशन, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण ों की उपलब्धता, डिजिटल एकीकरण और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी।

डॉ. दिनेश बर्थवाल को मिला ल्यूमिनरी लीडरशिप अवॉर्ड

देहरादून के प्रतिष्ठित विद्यालय दून इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ दिनेश बर्थवाल को EDUVISION 5.0 में ल्यूमिनरी लीडरशिप अवॉर्ड मिला है। डॉ दिनेश बर्थवाल ने दून इंटरनेशनल स्कूल सिटी कैंपस के मैनेजमेंट और टीचर्स को उनके लगातार सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि 'मैं बहुत खुशकिस्मत और आभारी हूँ कि मैं शिक्षा में इनोवेशन और एक्सीलेंस पर फोकस करने वाले ऐसे प्रेरणादायक इवेंट का हिस्सा बना, जो हमें स्टूडेंट्स के बड़े फायदे के लिए एक-दूसरे के साथ आइडिया शेयर करने का अनोखा मौका देता है।'

प्रशांत किशोर की कम्पनी 'आईपैक' पर ईडी का छापा

आईपैक पर ED कार्रवाई के बाद देशभर में चर्चा तेज

राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की इसी कंपनी आईपीएसी ने भारत की राजनीति में बड़े-बड़े कामों को अंजाम दिया है। भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आईपीएसी के दफ्तरों पर बड़ी छापेमारी की है।

राजनीतिक कंसलटेंट फर्म आईपैक के कारण राजनीति में बड़ा बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक आईपैक की खूब चर्चा हो रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह कंपनी आईपैक प्रशांत किशोर की मूल कंपनी है। राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की इसी कंपनी आईपैक ने भारत की राजनीति में बड़े-बड़े कामों को अंजाम दिया है। भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आईपैक के दफ्तरों पर बड़ी छापेमारी की है।

प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक का इतिहास लम्बा है

प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक का इतिहास लम्बा है। आईपैक के इतिहास को समझने से पहले प्रशांत किशोर के विषय में बताना जरूरी है। प्रशांत किशोर वर्तमान में बिहार प्रदेश के राजनेता हैं। प्रशांत किशोर की राजनीतिक पार्टी का नाम जन सुराज पार्टी है। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की करारी हार हुई है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर देश के अनेक राजनेताओं तथा राजनीतिक दलों को चुनाव जितवाने का बड़ा काम किया था।

वर्ष-2013 में प्रशांत किशोर ने डाली थी आईपैक की नींव

अब बात करते हैं राजनीति में बवाल मचाने वाली आईपैक फर्म की। आपको बता दें कि 8 साल पहले वर्ष-2013 में प्रशांत किशोर ने पॉलिटिक्स कंसलटेंट फर्म के रूप में आईपैक फर्म की नींव डाली थी। इस फर्म आईपैक की नींव प्रशांत किशोर ने अपने तीन साथियों प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह तथा विनेश चंदेल के साथ मिलकर डाली थी. शुरुआत में आईपैक फर्म नाम सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेस था, जो बाद में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के रूप में जानी जाने लगी। इस कंपनी का मकसद राजनीतिक दलों और नेताओं को चुनावी रणनीति, संगठन मजबूत करने और डेटा आधारित फैसलों में मदद करना है। आईपैक के जरिये ही प्रशांत किशोर ने 2014 में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक प्रचार-प्रसार का जिम्मा लिया था। इसके बाद बिहार चुनावों में नीतीश कुमार, पंजाब में अमरिंदर सिंह और आंध्र प्रदेश वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी के लिए भी प्रशांत किशोर की कंपनी ने काम किया था। इसके बाद से आईपैक पश्चिम बंगाल की सीएम ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करती है। दावा किया जाता है कि 2021 में प्रशांत किशोर ने आधिकारिक रूप से इस कंपनी को छोड़ दिया था। इसके बाद से ऋषि राज सिंह, विनेश चंदेल और प्रतीक जैन कंपनी के डायरेक्टर बन गए।

बहुत मोटी कमाई करती है आईपैक फर्म

इस फर्म का कमाई का सबसे बड़ा जरिया राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के लिए की जाने वाली कंसल्टेंसी है। यह कंपनी चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान पार्टियों को पूरी रणनीति देती है। इसमें उम्मीदवार चयन, जमीनी सर्वे, वोटर डेटा एनालिसिस, प्रचार रणनीति, सोशल मीडिया कैंपेन और मैसेजिंग तक शामिल होता है। राजनीतिक दल आईपैक को इसके लिए मोटी फीस देते हैं, जो प्रोजेक्ट और चुनाव के स्तर के हिसाब से तय होती है। आईपैक फर्म एक प्राइवेट पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, इसलिए इसकी सटीक नेटवर्थ सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बड़े चुनावी प्रोजेक्ट्स और लगातार बढ़ते काम को देखते हुए कंपनी की वैल्यू हजारों करोड़ों रुपये में आंकी जाती है। देश के बड़े राज्यों में चुनावी कैंपेन संभालने और लंबे समय तक पार्टियों के साथ काम करने से आईपैक की कमाई और प्रभाव दोनों लगातार बढ़े है।

क्यों मचा हुआ है आईपैक को लेकर राजनीतिक बवाल

आपको बता दें कि बृहस्पतिवार 8 जनवरी 2026 को हजारों करोड़ रुपये के कोयला घोटाले में प्रवर्तन निर्देशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख प्रतीक जैन के घर तथा प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा। मनी लॉन्ड्रिंग में 12 घंटे चली कार्रवाई के दौरान प. बंगाल की सीएम और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी आई-पैक के निदेशक जैन के घर पहुंच गई और फाइल लेकर निकल गई। इसके बाद सियासी विवाद बढ़ गया। ममता ने आरोप लगाया कि ईडी पार्टी के आंतरिक दस्तावेज, हार्डडिस्क और संवेदनशील डिजिटल डाटा जब्त कर रही है। उन्होंने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। उनकी पार्टी शुक्रवार को विरोध रैली भी निकालेगी। वहीं, ईडी ने कहा कि

किसी पार्टी कार्यालय की तलाशी में बाधा डाली और दस्तावेज जबरन नहीं ली गई। सीएम ममता ने कार्रवाई उठा ले गई।

कोलकाता हाईकोर्ट में पहुंच गया है आईपैक फर्म का मामला

इस पूरे प्रकरण को लेकर ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची है। कार्रवाई के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने भी हाईकोर्ट से केंद्र सरकार के खिलाफ मामला दर्ज कराने की अनुमति मांगी, जिस पर जस्टिस शुभ्रा घोष ने याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है। आई-पैक भी हाईकोर्ट ईडी में तलाशी की वैधता को चुनौती देगी। ने बृहस्पतिवार सुबह दिल्ली में 4 और बंगाल में 6 ठिकानों पर छापे मारे। इनमें कोलकाता में आई-पैक का कार्यालय और जैन का घर भी है। सूत्रों के अनुसार, जैन के खिलाफ घोटाले से जुड़े हवाला लेनदेन व नकदी डील के खास सबूत मिले हैं। मामला नवंबर, 2020 में सीबीआई की एफआईआर जुड़ा है। इस मामले में ईडी ममता भतीजे व सांसद अभिषेक बनर्जी से अवैध कोयला व्यापार से मिले फंड के पूछताछ कर चुकी है। दावा है कि से के बनर्जी भी लाभार्थी थे।

सूचना का अधिकार जन सशक्तिकरण और पारदर्शी शासन का मजबूत आधार- मुख्यमंत्री

आरटीआई अधिनियम के तहत सराहनीय कार्य करने वाले लोक सूचना तथा अपीलीय अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में आरटीआई अधिनियम (सूचना का अधिकार कानून) के लागू होने के 20 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में आरटीआई अधिनियम के तहत सराहनीय कार्य करने वाले 5 लोक सूचना अधिकारियों तथा 5 अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारियों को सम्मानित किया उनमें जिलाधिकारी बागेश्वर आकांक्षा कोंडे (तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार), अभिनव शाह मुख्य विकास अधिकारी देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी आयुष अग्रवाल, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के उपसचिव डॉ. प्रशांत, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एस.एस. चौहान, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनु सचिव राजन नैथानी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रामनगर वन प्रभाग कमला शर्मा, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से लियाकत अली खान और जिला विकास अधिकारी हरिद्वार वेद प्रकाश शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और पारदर्शी शासन व्यवस्था की आधारशिला है। इस अधिनियम ने शासन और नागरिकों के बीच विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही का एक नया अध्याय खोला है। उन्होंने कहा कि इस कानून ने प्रत्येक नागरिक को शासन की नीतियों, निर्णयों और कार्यप्रणाली को समझने, प्रश्न पूछने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की शासन व्यवस्था में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की नई कार्यसंस्कृति विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस, ई-ऑफिस, ऑनलाइन पोर्टल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जन-सुनवाई जैसे माध्यमों ने शासन और जनता के बीच संबंध को और मजबूत बनाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी और जनोन्मुखी शासन व्यवस्था की दिशा में सतत कार्य कर रही है। राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है और अधिकांश सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे नागरिकों को जानकारी और सेवाओं की उपलब्धता में सुगमता आई है। मुख्यमंत्री ने आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल और आयोग की हाइब्रिड सुनवाई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इससे न्याय प्रक्रिया और भी सुलभ हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य सूचना आयोग में 13 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में केवल 700 प्रकरण लंबित हैं, जो आयोग की दक्षता का प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने नागरिक अधिकारों की रक्षा में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही इसके उपयोग में जिम्मेदारी भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में इस अधिनियम का दुरुपयोग देखा गया है, जिस पर रोक लगाने के लिए जनजागरूकता बढ़ाना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विभाग उन सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रदर्शित करे जिनकी बार-बार मांग की जाती है, ताकि नागरिकों को स्वतः जानकारी मिल सके और पारदर्शिता बढ़े।

लखवाड़ परियोजना को समय पर पूरा करने का अल्टीमेटम

राज्य की बहुप्रतीक्षित और रणनीतिक महत्व की लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने परियोजना की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, ढिलाई या अनावश्यक विलंब कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को आपसी समन्वय के साथ तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना से जुड़ी तकनीकी स्वीकृतियों, आवश्यक आरेखों, मानव संसाधन और निर्माण सामग्री की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही, समयसीमा के अनुरूप चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार कर नियमित समीक्षा किए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि परियोजना की प्रगति पर स्वयं उनके स्तर से कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

राज्य की बहुप्रतीक्षित और उच्च प्राथमिकता वाली लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं और सभी संबंधित संस्थानों को समन्वय के साथ कार्यों में तेजी लानी होगी। उन्होंने सभी विभागों के साथ नियमित बैठकें कर प्रगति की समीक्षा करने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान परियोजना से जुड़े विभिन्न संस्थानों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने परियोजना से संबंधित सभी प्रकार के आरेख समय से तैयार कर केंद्रीय जल आयोग से उनके पुनरीक्षण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना और स्पष्ट समयसीमा तय करने पर जोर दिया। साथ ही, दक्ष मानव संसाधन, आवश्यक मशीनरी और निर्माण सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जल विद्युत से संबंधित यांत्रिक आरेख शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी आवश्यक अध्ययनों को समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए यूजेवीएनएल और जिला प्रशासन को प्रभावितों और सभी संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने को कहा, ताकि किसी भी स्तर पर बाधा उत्पन्न न हो। मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव ऊर्जा को अपने स्तर पर पंद्रह दिन में एक बार कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना की प्रगति पर उनके स्तर से भी नियमित और कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही, विभिन्न स्वीकृतियों के लिए संबंधित मंत्रालयों से निरंतर समन्वय कर फाइल प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि यमुना नदी पर स्थित लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बांध की ऊंचाई 204 मीटर है और इसकी जीवित भंडारण क्षमता 330.40 मिलियन घन मीटर होगी। परियोजना से 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता विकसित की जानी है। बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुन्दरम, यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल, केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बड़े शहरों में आवारा कुत्तों और गोवंश पर सख्ती, मुख्य सचिव ने मांगी रिपोर्ट

बड़े शहरों में आवारा कुत्तों और बेसहारा गोवंश की बढ़ती समस्या को लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में संबंधित विभागों के साथ बैठक कर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। उन्होंने सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले स्थानों से आवारा कुत्तों और गोवंश को हटाने के लिए यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तलब की। मुख्य सचिव ने देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और काशीपुर जैसे बड़े शहरों में न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को क्षेत्रवार नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिम्मेदारी तय कर त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा कुत्तों और गोवंश को लेकर की गई कार्रवाई की जानकारी ली और कहा कि दुर्घटना संभावित और संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर ठोस कदम उठाए जाएं। मुख्य सचिव ने बेसहारा गोवंश के लिए कांजीहाउस तैयार करने और उनके संचालन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने परिवहन सचिव को निर्देश दिए कि सभी बस टर्मिनलों, रेलवे स्टेशनों और उनके आसपास स्थानीय निकायों के सहयोग से आवारा पशुओं पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। साथ ही, उन्होंने बेसहारा पशुओं को गोद लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाने की बात कही। उन्होंने पालतू पशु रखने वालों के लिए क्या करें और क्या न करें संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे समस्या के स्थायी समाधान में मदद मिलेगी।

उत्तरांचल प्रेस क्लब, प्रदेश की लोकतांत्रिक चेतना का सशक्त मंच है: पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री ने उत्तरांचल प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को दिलाई शपथ

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब, परेड मैदान, देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री ने सभी नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तरांचल प्रेस क्लब, प्रदेश की लोकतांत्रिक चेतना का सशक्त मंच है। उत्तरांचल प्रेस क्लब ने हमेशा अपनी गरिमा, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाए रखा है। उन्होंने कहा पत्रकारिता, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यह सरकारों को उत्तरदायी, समाज को जागरूक और आम नागरिक को सजग करता है। स्वतंत्र, जागरूक और जिम्मेदार पत्रकारिता, सरकार और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल युग में, सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाएँ तेजी से फैल रही हैं, ऐसे में पत्रकारों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। सही तथ्यों के साथ निष्पक्ष और जिम्मेदार रिपोर्टिंग ही समाज को भ्रम से बचा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड के पत्रकारों ने हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में साहस के साथ अपना काम किया है। उन्होंने कहा पत्रकारों की कलम में वह शक्ति है, जो समस्याओं को उजागर करने के साथ-साथ समाधान का मार्ग भी प्रशस्त करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। पत्रकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आकस्मिक सहायता एवं आवासीय योजनाओं को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के साथ दिया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के अंतर्गत अनेक वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। पत्रकार पेंशन में वृद्धि के साथ-साथ, विभिन्न जिलों से देहरादून आने वाले पत्रकारों के लिए सूचना विभाग के माध्यम से आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरांचल प्रेस क्लब के भवन निर्माण के मुद्दे को उन्होंने स्वत: ही कैबिनेट में रखा। जिसपर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा जल्द ही यह भवन एक मॉडल भवन के रूप में बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना के अंतर्गत पत्रकार कल्याण कोष का बजट 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है। उन्होंने कहा उत्तराखंड प्रत्येक क्षेत्र की भांति जनसंचार के क्षेत्र में भी अपनी एक नई पहचान स्थापित करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया सेंटरों के आधुनिकीकरण और प्रेस क्लबों के सशक्तिकरण पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा 2026-27 के सामान्य बजट में भी मीडिया सेंटरों को लेकर प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा इससे आने वाले समय में अन्य जिलों में भी पत्रकारों को अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के प्रति उनका भी ऋण और उत्तरदायित्व है। उन्होंने कहा वो स्वयं भी सामान्य परिस्थितियों से उठकर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहेंगे। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने अपनी कर्तव्यों का निर्वहन पहले भी किया है और आगे भी करते रहेंगे।

उत्तरांचल प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अजय सिंह राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा पत्रकारों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा पत्रकार, पत्रकारिता के साथ अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने उत्तरांचल प्रेस क्लब के भवन निर्माण को लेकर कैबिनेट में हुए फैसले के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अजय सिंह राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री गजेन्द्र सिंह नेगी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सोबन सिंह गुसाई, महामंत्री श्री योगेश सेमवाल, संयुक्त मंत्री श्री शिवेश शर्मा, श्रीमती मीना नेगी, कोषाध्यक्ष श्री मनीष डंगवाल, सम्प्रेक्षक श्री विजय जोशी एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री वीरेन्द्र डंगवाल 'पार्थ', श्री मनमोहन लखेड़ा, श्रीमती रश्मि खत्री, सुलोचना पयाल, श्री मनोज सिंह जयाड़ा, श्री हरीश थपलियाल, श्री मनबर सिंह रावत, श्री ओम प्रकाश जोशी, श्री हिमांशु जोशी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर विधायक श्री खजान दास, मेयर श्री सौरभ थपलियाल, दायित्वधारी डॉ. देवेंद्र भसीन, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

"जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" अभियान के माध्यम से लाखों नागरिकों तक पहुँची धामी सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, त्वरित समाधान और पारदर्शी प्रशासन का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। 09 जनवरी 2026 तक आयोजित शिविरों के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि सरकार सीधे जनता के द्वार तक पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी 13 जनपदों में अब तक 297 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 2,13,341 नागरिकों ने प्रत्यक्ष सहभागिता की। इन शिविरों के माध्यम से जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए 24,247 शिकायतें प्राप्त की गई, जिनमें से 16,458 शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन कैंपों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाओं से जोड़ने का कार्य भी प्रभावी ढंग से हुआ है। विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों हेतु 33,158 आवेदन प्राप्त किए गए, वहीं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से 1,21,378 नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सेवा, समाधान और संवेदनशीलता का अभियान है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला प्रत्येक नागरिक भी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि जनपदवार आयोजित कैंपों में अल्मोड़ा, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, उधम सिंह नगर, देहरादून सहित सभी जिलों में व्यापक जनभागीदारी देखने को मिली है, जो इस बात का प्रमाण है कि जनता सरकार पर भरोसा कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों और आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ जनता के द्वार तक पहुँचेगी और सुशासन, पारदर्शिता एवं जनकल्याण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए रखेगी।

आयुष्मान को लेकर लाभार्थियों को किया जागरूक

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सरकारी व निजी चिकित्सा संस्थानों में चलाया गया जागरूकता अभियान

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से देहरादून जनपद के विभिन्न सरकारी व निजी चिकित्सा संस्थानों में आयुष्मान जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस अवसर पर अस्पताल में भर्ती मरीज, उनके तीमारदार व ओपीडी में आए लोगों को आयुष्मान व एबीडीएम की विभिन्न जानकारियों से रूबरू कराया गया। साथ ही उन्होंने आयुष्मान योजना की जानकारियों से युक्त पंपलेट व अन्य प्रचार सामाग्री वितरित की गई।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद सिंह ह्यांकी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी आईएएस के निर्देशों के अनुपालन में आयुष्मान योजना व आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की महत्वपूर्ण जानकारियों को जन-जन तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक आईईसी नवीन शुक्ला, नवीन चमोली व एबीडीएम के प्रणव शर्मा द्वारा राजधानी के विभिन्न सरकारी व निजी चिकित्सा संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम में आयुष्मान के प्रचार के साथ ही विशेषतौर पर 70 वर्ष या उससे अधिक आयुवर्ग के लोगों के लिए संचालित वय वंदना कार्ड के बारे में विस्तार से समझाया गया। जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं बने उनसे कार्ड बनाने की अपील की गई। ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें योजना का लाभ मिल सके। साथ ही सड़क हादसे में घायल हुई पीड़ितों को डेढ लाख या एक सप्ताह तक जो भी पहले हो के तत्काल उपचार के बारे में जानकारियां दी गई। एबीडीएम के तहत आभा आईडी के महत्व, स्वास्थ्य रिकार्ड का डिजिटलाइजेशन व स्कैन एंड शेयर की व्यवस्था के लाभ व किसी जानकारी, सुझाव शिकायत के निस्तारण के लिए जारी टोल फ्री नंबर के बारे में भी बताया गया।

इस मौके पर अस्पतालों में आयुष्मान योजना को लेकर मरीजों को भ्रमित करने वाले तत्वों से सावधान रहने की अपील करती व योजना की गुणवत्ता व सार्वभौमिकता युक्त प्रचार सामाग्री भी कार्यक्रम वितरित की गई।

धार्मिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों पर देहरादून में राउंड टेबल डायलॉग

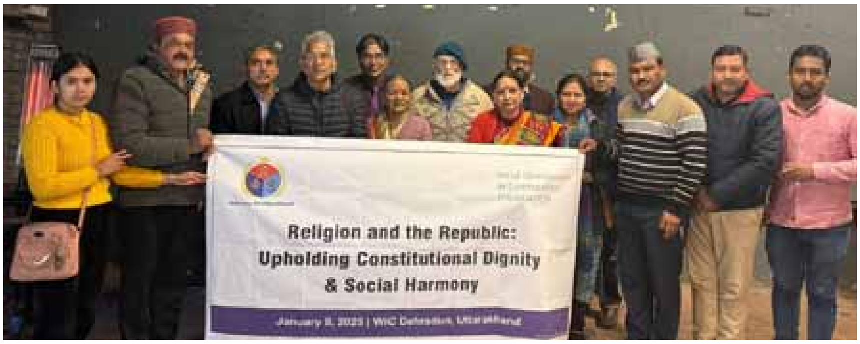

देहरादून स्थित वर्ल्ड इंटेग्रिटी सेंटर में सशस्त्र सैनिक एवं अर्धसैनिक बल समुदाय उत्तराखंड के विभिन्न वेटरन्स संगठनों तथा एसडीसी फाउंडेशन उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण राउंड टेबल डायलॉग का आयोजन किया गया। इस राउंड टेबल डायलॉग का विषय धार्मिक सद्भाव, संवैधानिक मर्यादा और सामाजिक समरसता रहा। कार्यक्रम में देहरादून शहर के सैनिक एव अर्धसैनिक वेटरन्स, विभिन्न सामाजिक वर्गों, व्यवसायों, आयु समूहों, धर्मों तथा महिलाओं सहित प्रबुद्ध नागरिकों ने सहभागिता की।

चर्चा का उद्देश्य समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण के बीच संवाद, आपसी समझ और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना रहा। ब्रिगेडियर सर्वेश दत्त (पहाड़ी) डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल विमर्श के सह-संयोजक थे। कार्यक्रम में आईजी एस.एस. कोठियाल, मधुरलता अग्रवाल, अनिता नौटियाल, सुजाता पॉल मालिहा, कर्नल राजीव रावत, लेफ्टिनेंट कर्नल कैलाश चंद्र देवरानी, हवलदार निरंजन सिंह चौहान, सोलोमन दास, जितेंद्र सहरावत, डॉक्टर अपूर्व मवाई और दिनेश चंद्र उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि भारत केवल एक भू-भाग नहीं, बल्कि संविधान, नैतिकता और सह-अस्तित्व पर आधारित एक विचार है। भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान सम्मान देता है और देश की धर्मनिरपेक्ष भावना स्वतंत्रता के समय से ही इसकी मूल आत्मा रही है।

चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि आज के दौर में समस्या धर्म से नहीं बल्कि उसके राजनीतिक दुरुपयोग से हो रही है। धर्म का उद्देश्य मानवता, करुणा और आत्मसंयम है, लेकिन जब इसका उपयोग भय और नफरत फैलाने के लिए किया जाता है, तो समाज में विभाजन बढ़ता है। राउंड टेबल डायलॉग में स्पष्ट किया गया कि यह बैठक किसी निष्कर्ष को थोपने या किसी आस्था पर निर्णय देने के लिए नहीं, बल्कि उन सामाजिक प्रश्नों पर संवाद स्थापित करने के लिए आयोजित की गई है, जिन पर अक्सर खुलकर चर्चा नहीं हो पाती। हिंदू धर्म और हिंदुत्व के अंतर पर भी विचार रखा गया। वक्ताओं ने कहा कि हिंदू धर्म एक प्राचीन, उदार और प्रश्नशील परंपरा है, जबकि हिंदुत्व एक आधुनिक राजनीतिक विचारधारा है। इस अंतर को न समझना सामाजिक भ्रम और तनाव का कारण बन रहा है। पूर्व सैनिक समुदाय की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि वर्दी किसी धर्म की नहीं, बल्कि संविधान की होती है। युद्धभूमि पर कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं, बल्कि केवल भारतीय सैनिक होता है। इसलिए धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति का सैन्य मूल्यों से कोई मेल नहीं है। मीडिया, नागरिक समाज और बौद्धिक वर्ग से भी आत्ममंथन करने का आहवान किया गया। यह कहा गया कि समाज में संतुलन, विवेक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सभी वर्गों को जिम्मेदारी निभानी होगी। राउंड टेबल डायलॉग का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि गणराज्य आस्था से नहीं डरता, बल्कि आस्था के नाम पर विवेक के त्याग से डरता है। परिचर्चा के अंत में यह निर्णय लिया गया कि इस संवाद को आगे भी जारी रखा जाएगा और कार्यशालाओं व नागरिक सहभागिता के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में वेटरन्स और समाज के बीच में सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक चेतना को मजबूत करने के और प्रयास किए जाएंगे।

पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं

पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड दीपम सेठ ने पुलिस मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारियों, शाखा प्रभारियों एवं कर्मचारियों से भेंट कर उन्हें नववर्ष 2026 की शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर डीजीपी ने विगत वर्ष के दौरान अनुभागों के बीच बेहतर समन्वय एवं कर्मियों की मेहनत के परिणामस्वरूप कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, चारधाम यात्रा सुरक्षा तथा जनसेवा से जुड़े कार्यों में उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों के कल्याण से संबंधित विषयों पर सुझाव भी प्राप्त किए। उन्होंने सभी से टीम भावना, अनुशासन एवं समर्पण के साथ कार्य करने का आहवान करते हुए उत्तराखण्ड पुलिस परिवार के समस्त परिजनों के सुख, स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

आपदा प्रबंधन सामूहिक जिम्मेदारी, सभी विभाग समन्वित रूप से करें कार्य- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने किया 'शीतलहर पूर्व तैयारी' विषय पर कार्यशाला का शुभारंभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, हाथीबड़कला में 'शीतलहर पूर्व तैयारी' विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने शीतलहर, बाढ़, मॉक अभ्यास, हवाई यातायात सहायता की एस.ओ.पी., आपदा प्रबंधन विभाग के नववर्ष कैलेंडर 2026 एवं आपदा प्रबंधन हस्तपुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवा आपदा मित्रों एवं वर्ष 2025 में आपदा के दौरान राहत एवं बचाव में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। आपदा प्रबंधन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए चार वाहनों का भी मुख्यमंत्री ने फ्लैग ऑफ किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा प्रबंधन किसी एक विभाग की नहीं, बल्कि समस्त प्रशासन, स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी संगठनों और आम जनता की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एक प्रमुख एजेंडा बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार भी उन्हीं के मार्गदर्शन में आपदा प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। राज्य में ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग एवं अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेंसर लगाने, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम एवं आधुनिक रैपिड रिस्पॉन्स टीमों के गठन जैसे कदमों से आपदा जोखिम को घटाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में हिमस्खलन (एवलांच) एक गंभीर प्राकृतिक जोखिम है। राज्य के कई क्षेत्र हिमस्खलन की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में पर्यटन, तीर्थाटन एवं पर्वतारोहण गतिविधियों को सुरक्षित बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने, आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग, प्रशिक्षित रेस्क्यू बलों की तैनाती तथा सुरक्षित पर्यटन प्रोटोकॉल को और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शीतलहर और अत्यधिक हिमपात से उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए भी राज्य में कई ठोस और व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं। सभी जिलों को अर्ली वार्निंग सिस्टम से जोड़ा गया है और अलाव, रैन बसेरों तथा कंबलों की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश भी जिलाधिकारियों को दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन आपस में बेहतर तालमेल बनाए रखें और अर्ली वार्निंग सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ करते हुए शीतलहर तथा हिमपात वाले क्षेत्रों में समय पर चेतावनी और आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करें। शीतलहर के दौरान हाइपोथर्मिया, जुकाम, फ्लू, निमोनिया जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिला अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और मोबाइल मेडिकल टीमों को सक्रिय रखना होगा। विशेष रूप से सीमांत और ऊँचाई वाले क्षेत्रों में आवश्यक दवाइयों, हीटिंग उपकरणों एवं प्राथमिक उपचार सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 'युवा आपदा मित्र' एवं 'आपदा सखी' जैसी पहल को और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला के माध्यम से शीत ऋतु के दौरान होने वाली संभावित चुनौतियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा तथा विभागों के मध्य समन्वय को मजबूत किया जाएगा। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि शीतलहर धीरे-धीरे अपना प्रभाव दिखाती है, परंतु इसका असर भयावह होता है। यह आमजन की स्वास्थ्य सेवाओं और विशेष रूप से संवेदनशील लोगों के जनजीवन को प्रभावित करती है। शीतलहर प्रबंधन को हमें केवल मौसमी प्रबंधन की चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक और सामाजिक दायित्व के रूप में देखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य में आपदा प्रबंधन को सशक्त, संगठित और नीति-आधारित स्वरूप देने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेन्द्र सिंह, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहिला, सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, आनंद स्वरूप, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन) राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो. ओबैदुल्लाह अंसारी एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून मे सांसद खेल महोत्सव का समापन, सीएम धामी व सांसद नरेश बंसल ने विजेता टीमो को किए पुरस्कार वितरित

पूरे देशभर में हमारे प्रधानमंत्री जी खेलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, खिलाड़ीयो को मिल रहा नया प्लेटफार्म: *डॉ. नरेश बंसल*

देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित ओल्ड मल्टीपरपेज हॉल, परेड ग्राउंड में गुरुवार को डा. नरेश बंसल के द्वारा आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से समारोह में शिरकत की और खिलाड़ियों से संवाद किया व चर्चा वार्ता की।

इस अवसर पर राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खिलाड़ियों को संबोधित किया व विभिन्न प्रतियोगीताओ के विजेता खिलाड़ीयो को पुरस्कार वितरित किए। डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव के आयोजन में खेल और युवा कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग सबने मिलकर समन्वय बनाकर काम किया है। तीन चरणों में खेल पूर्ण हुए हैं, पहले न्याय पंचायत स्तर पर हुए, 48 न्यायपंचायतों की 170 टीमों ने भाग लिया उसमें और आठ खेल हमने इसमें चयनित किए थे। इसमें हजारों नए युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रधानमंत्री जी ने इसमें प्रेरणादाई भाषण इसमें दिया है। इसी प्रकार जैसे पूरे देशभर में हमारे प्रधानमंत्री जी खेलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे उत्तराखण्ड में मा० मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और नेतृत्व से यह सब कार्य सम्पन्न हो रहे हैं। डा. नरेश बंसल ने सीएम धामी के साथ विजेताओ को पुरस्कार दिए।

कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की।

इस अवसर पर आयोजन में सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह जी, राज्यमंत्री विनोद उनियाल जी, विषेश सचिव अमित सिन्हा जी, आदी जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, खेल संघों के पदाधिकारी, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे।

प्रकृति रक्षा, पर्यावरण चेतना और एकता का संदेश देगी राष्ट्रीय उत्तरायणी

नई दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में सुखी परिवार फाउंडेशन के कार्यालय में आज 22 वें राष्ट्रीय उत्तरायणी महोत्सव आयोजन समिति की बैठक संपन्न हुई।

उत्तरायणी आयोजन समिति की इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुखी परिवार फाउंडेशन के संस्थापक और सुप्रसिद्ध जैन संत डॉ. गणि राजेन्द्र विजय जी महाराज ने कहा कि उत्तरायण पर्व देश को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सभी दृष्टि से एकाकार करता है। पर्वतीय लोकविकास समिति ने दो दशक से इस महापर्व को प्रकृति, पर्यावरण और राष्ट्रीय एकता से जोड़कर राष्ट्रीय अभियान बनाया है। ऐसे जनजागरण इसके आयोजन यदि समाज और सरकार सब ओर से सहयोग पाएं तो व्यापक संदेश जाएगा। पर्वतीय लोकविकास समिति के परामर्शदाता CA राजेश्वर पैन्यूली ने कहा कि उत्तरायणी प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा,उमंग, उत्साह और सकारात्मकता का पर्व है। धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के विजन के साथ इसकी व्यापक अवधारणा अनुकरणीय है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता नेपाल सिंह ने कहा कि उत्तरायणी अब उत्तराखंड का ही सर्वमान्य पर्व नहीं बल्कि देश का भी लोकप्रिय पर्व बन गया है।

सुखी परिवार फाउंडेशन के महासचिव तपन प्रकाश ने कहा कि उत्तरायणी के राष्ट्रीय अभियान को इस बार ल्युटियन जोन में चर्चित और भव्य बनाना है।

पर्वतीय लोकविकास समिति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय उत्तरायणी अभियान के संयोजक प्रो. सूर्य प्रकाश सेमवाल ने कहा कि हमने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और दिल्ली सरकार के संस्कृति मंत्रालय को राष्ट्रीय उत्तरायणी की अवधारणा का प्रस्ताव महीने भर पूर्व भेज दिया था। 10 जनवरी को प्रेस क्लब में राष्ट्रीय उत्तरायणी अभियान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

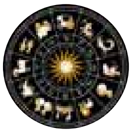
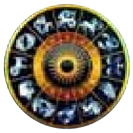

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि– काफी समय से रुके हुए कुछ काम पूरे होंगे और आप कुछ नया करने की भी कोशिश करेंगे। जिससे आपकी सोच में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखना और उनका आदर-मान करना आपको मन का सुकून देगा। चुनौतियां भी सामने खड़ी मिलेंगी। अगर उनका डटकर मुकाबला किया तो जीत तय है।

वृषभ राशि– सफलता दायक समय बना हुआ है। कुछ खास लोगों से मेल-मुलाकात होगी। और बातचीत के जरिए कोई बाधा भी दूर होगी। सामाजिक दायरा और ज्यादा बढेगा। बच्चों के साथ कुछ समय बिताने से मानसिक सुकून बना रहेगा। आर्थिक स्थिति को लेकर कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन चिंता न करें जल्दी ही आप उस पर काबू भी पा लेंगे।

मिथुन राशि– आपका स्वाभिमान और आत्मविश्वास हर परिस्थिति में मेहनत करने की क्षमता देगा और आपके रुके हुए काम थोड़े से प्रयास से बन जाएंगे। समाज में भी आपका मान-सम्मान बना रहेगा। कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें। इससे मानसिक शांति बनी रहेगी। अपनी जीवनशैली को अनुशासित रखना जरूरी है।

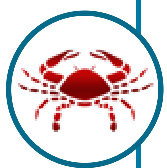

कर्क राशि– ग्रहों की स्थिति सुखद बनी हुई है। करीबी लोगों के साथ फायदेमंद योजनाओं पर विचार-विमर्श होगा। आज आप अपनी मेहनत और समझदारी से वह सब हासिल कर सकते हैं, जिसकी आपने तमन्ना की है। मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेगा। कुछ न कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। नकारात्मक परिस्थितियों को गुस्से की बजाय शांत तरीके से निपटाएं तो ज्यादा बेहतर है।

सिंह राशि– कोई मनचाहा काम बनेगा। आपके विचारों से लोग सहमत रहेंगे, जिससे गतिविधियां और ज्यादा व्यवस्थित हो जाएंगी। कुछ समय आत्मचिंतन में भी जरूर बिताएं, इससे आप अपने काम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। भाइयों के साथ संबंध बिगड़ने से बचाएं। कभी-कभी मनमर्जी और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास की वजह से धोखा खा सकते हैं।

कन्या राशि– फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी गतिविधियों के लिए समय अनुकूल है। लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन जरूर लें। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका खास योगदान रहेगा। किसी नजदीकी संबंधी के साथ मेल-मुलाकात के अवसर बनेंगे। दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें। और अपने काम से मतलब रखें।

तुला राशि– ग्रहों की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। रुके पड़े किसी मुद्दे या काम को आप कुशलता और शांति से निपटा पाएंगे। युवाओं का इंटरव्यू में बेहतरीन प्रेजेंटेशन रहेगा। सोसाइटी और सामाजिक गतिविधियों में भी आपका योगदान रहेगा। वक्त के अनुसार खुद में भी बदलाव लाना जरूरी है। कई बार अपने उसूलों पर ज्यादा अड़िग रहना भी नुकसान दे सकता है।

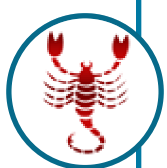

वृश्चिक राशि– दिनचर्या बहुत व्यस्त रहेगी। आप अपनी योग्यता और प्रतिभा से कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे। घर के सदस्यों का सहयोग और सलाह भी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आपके व्यक्तित्व में आ रहा सकारात्मक बदलाव दूसरों के लिए चर्चा का विषय बनेगा। खर्चों में बढ़ोतरी भी हो सकती है इसलिए फाइनेंस से जुड़ी गतिविधियों में बहुत सचेत रहना होगा।

धनु राशि– कोई योजना बन सकती है, जिसमें आपको अपनी योग्यता और काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। कोई आर्थिक योजना सफल होने से मन प्रसन्न रहेगा। वाहन या कोई कीमती वस्तु खरीदने की योजना है, तो आज फैसला लेना उचित रहेगा। घरेलू मामलों में बिना सोचे-समझे भावनाओं में बहकर किया गया खर्च आपके बजट को बिगाड़ सकता है।

मकर राशि– पारिवारिक या व्यवसाय से जुड़ा कोई भी मामला आपसी समझदारी और सकारात्मक बातचीत से सुलझ सकता है। कई गतिविधियां आपको व्यस्त रखेंगी और संपर्क दायरा भी बढेगा। रुकी हुई बड़ी पेमेंट मिल जाने से आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आएगा। बेकार की गॉसिप और विवादों से दूर रहें। बीती हुई नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें।

कुंभ राशि– यह समय मौज-मस्ती में बीतेगा और किसी नजदीकी संबंधी के यहां समारोह में जाने का निमंत्रण भी मिलेगा। काफी समय बाद लोगों से मिलना-जुलना खुशी देगा। किसी के साथ चल रहा मनमुटाव आपसी विवेक और समझदारी से दूर हो जाएगा। इनकम के साथ-साथ खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी, जिसकी वजह से सेविंग करना मुश्किल होगा।

मीन राशि– किसी भी परेशानी की स्थिति में अपने नजदीकी मित्र से जरूर विचार-विमर्श करें, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। अगर स्थान परिवर्तन की कोई योजना बन रही है, तो उसे अमल में लाने का अच्छा समय है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। फोन या ऑनलाइन गतिविधियों में समय व्यर्थ न करें और अपने काम पर फोकस रखें।

ऑस्कर 2026 में भारत का जलवा! इन 4 फिल्मों ने मचाया तहलका, क्या इस बार अपना देश जीतेगा बेस्ट पिक्चर?

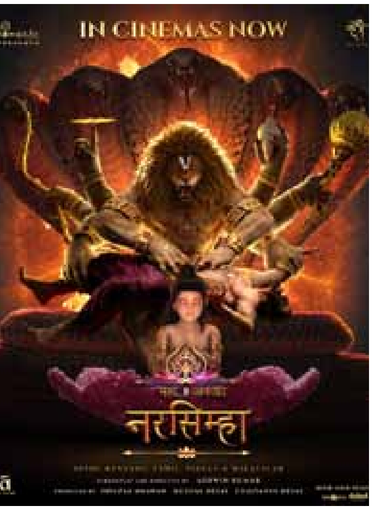

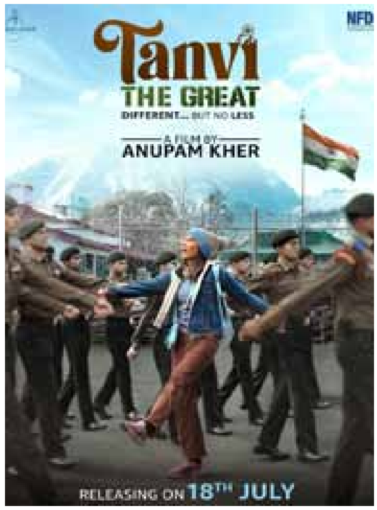

ऑस्कर 2026 को लेकर दुनियाभर के सिनेप्रेमियों में एक्साइटमेंट चरम पर है। 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए फाइनल नॉमिनेशन का ऐलान 22 जनवरी 2026 को किया जाएगा। इससे पहले 9 जनवरी 2026 को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने उन 201 फीचर फिल्मों की रिमाइंडर लिस्ट जारी की, जो बेस्ट पिक्चर कैटेगरी के लिए मान्य मानी गई हैं।

इस लिस्ट में चार भारतीय फिल्मों का शामिल होना देश के लिए गर्व की बात है और यह दर्शाता है कि भारतीय सिनेमा लगातार ग्लोबल मंच पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।

लिस्ट में कौन-कौन सी भारतीय फिल्में?

एकेडमी की यह रिमाइंडर लिस्ट शुरुआती स्टेज की होती है। इसमें वही फिल्में जगह बनाती हैं, जो थिएटर रिलीज और अन्य तकनीकी मानकों को पूरा करती हैं। लास्ट नॉमिनेशन इसी लिस्ट में से चुने जाते हैं।

भारत की जिन चार फिल्मों ने इस बार जगह बनाई है, वे हैं:

महावतार नरसिंह

अश्विन कुमार के निर्देशन में बनी यह मल्टीलिंगुअल एनिमेटेड फिल्म भक्ति, एक्शन और पौराणिक कथा का शानदार मेल है। यह एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत मानी जा रही है।

कांतारा: ए लीजेंड-चैप्टर 1

ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और स्टारर यह फिल्म 2022 की सुपरहिट 'कांतारा' की प्रीक्वल है। कहानी तुलुनाडु क्षेत्र में दैव परंपरा और प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों को उजागर करती है। 2025 में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता रही।

तन्वी द ग्रेट

अनुपम खेर के निर्देशन में बनी यह प्रेरणादायक फिल्म एक ऑटिस्टिक लड़की तन्वी रैना की कहानी कहती है, जो अपने दिवंगत पिता का भारतीय सेना में सेवा करने का सपना पूरा करना चाहती है।

टूरिस्ट फैमिली

तमिल भाषा में बनी यह फिल्म नए निर्देशक अभिशन जीविन्थ की पहली पेशकश है। फिल्म पारिवारिक रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं को खूबसूरती से दर्शाती है।

इन फिल्मों की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय सिनेमा अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव छोड़ रहा है।

ऑस्कर जीतने पर क्या मिलता है?

ऑस्कर अवॉर्ड जीतने पर एकेडमी की ओर से कोई नकद इनाम नहीं दिया जाता। विजेता को ऑस्कर ट्रॉफी दी जाती है, जो सोने की परत चढ़ी कांस्य से बनी होती है।

एकेडमी के नियमों के अनुसार, इस ट्रॉफी की आधिकारिक कीमत सिर्फ 1 अमेरिकी डॉलर (करीब 90 रुपये) मानी जाती है। विजेता इसे खुले बाजार में बेच नहीं सकते। यदि कभी बेचना हो, तो सबसे पहले इसे एकेडमी को उसी कीमत पर ऑफर करना जरूरी होता है।

हालांकि, मैन कैटेगरी के नॉमिनी को अक्सर ब्रांड्स द्वारा दिए जाने वाले लग्जरी गिफ्ट बैग्स मिलते हैं, जिनकी कीमत हाल के सालों में 2 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा बताई गई है। ऑस्कर जीतने का सबसे बड़ा फायदा होता है करियर में जबरदस्त उछाल, ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मौके और फिल्मों की फीस में भारी बढ़ोतरी।

कब और कहां होंगे ऑस्कर 2026?

98वें एकेडमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2026) का आयोजन 15 मार्च 2026 यानी रविवार को किया जाएगा। यह अवॉर्ड फंक्शन डॉल्बी थिएटर, ओवेशन हॉलीवुड, लॉस एंजेलिस में होगा। अमेरिका में समारोह एबीएस चैनल पर लाइव प्रसारित होगा और हुलू पर स्ट्रीम किया जाएगा। भारत में ऑस्कर 2026 का लाइव टेलीकास्ट 16 मार्च 2026 को होगा। भारतीय दर्शक इसे स्टार मुवी, स्टार सलेक्ट और जियो हॉटस्टार पर लाइव देख सकेंगे। भारत में लाइव टाइमिंग रहेगी सुबह 4:30 बजे से 7:30 बजे।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

Silkyara™

Pahad ki Mahilaon Dwara Banaya Gaya

Pure & Natural

A2 Badri Cow Ghee

A2 Beta Protein

Bilona Method

Immunity Booster

fssai
22623030001586

UDYOG AADHAR MSME
UK050061483

THE DOON HIMALAYAN AGRO FOODS
Dalanwala, Dehradun
Customer Care - 7409782771

Available at

KUMAR SWEETS
Sahastradhara Road,
Near Crossing, Dehradun
7017180869

PLANET JR
Panditwadi,
Chakrata Road, Dehradun
9897477151